Title: Request to reconsider the privatisation of the MECON Ltd., Ranchi.

श्री राम टहल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अंतर्राट्रीय ख्याति प्राप्त भारत सरकार की इंजीनियरिंग परामर्शदाता संस्था मेकान लिमिटेड रांची में स्थित है। सरकार इस संस्था का निजीकरण करने की सोच रही है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। इसका विरोध पूरे झारखंड क्षेत्र में वहां के अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से भी हो रहा है। मेकॉन 1978 तक स्टील अथोरिटी का एक भाग रहा है। यह खासतौर पर लौह और इस्पात के क्षेत्र में डिजाइन एवम् इंजीनियरिंग के कार्यकलापों के अंजाम देने के ख्याल से भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। देश-विदेश में फैले अपने विशाल नेटवर्क, बौद्धिक क्षमता एवम् विलक्षण अभियांत्रिकी प्रतिभा से प्राप्त अपनी विशिष्ट उपलब्धियों द्वार, मेकॉन ने तकनीकी निर्माण के क्षेत्र में राट्र को गौरवान्वित एवम् समृद्ध किया है। मगर आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह संस्था जो बराबर लाभ मे रही है, करोड़ों रुपए इससे भारत सरकार को मिलते रहे हैं, इसका निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा सरकारी केन्द्र सरकार के अनेक अति संवेदनशील प्रोजेक्ट प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु आदि क्षेत्रों में काम किया जाता रहा है और अभी भी यह कर रही है। इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो जनहित में है, उनका भी कार्य इसने किया है। हम आज भी, इसरो के द्वितीय लंच पैड, जल सेना के सीवर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग के यूरेनियम आदि गोपनीय किस्म के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरी कंसलटेंसी कम्पनी के अलावा निजी क्षेत्र की कम्पनीज से कराना खतरनाक एवम् राट्र हित के विरूद्ध साबित हो सकता है। यह संस्था पिछले दो सालों से नुकसान में चल रही है, लेकिन ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो नुकसान में जा रही हैं। यह संस्था झारखंड के निर्माण में लगी हुई है। वहां इसके द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसके द्वारा निशुल्क शिक्षा एवम् सुविधा मुहैया कराने, आदि वासी क्षेत्रों में वहां से सम्बन्धित प्रोजेक्ट जैसे ग्रामीण सड़कें, पुल, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य आदि का काम भी यह कर रही है। यह झारखंड में, जो अभी नया राज्य बना है, अवस्थित है।

मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस संस्था को कम से कम दो साल का समय दिया जाए। इस अवधि में यह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका निजीकरण करना उचित नहीं होगा। मैं इस संस्था के निजीकरण किए जाने का विरोध करता हूं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे और निजीकरण न करे।